भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1386
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन

1386 # श्री नीरज डांगी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अब तक हुई प्रगति का जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य के कितने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल अभिलेख प्रबंधन तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं पूर्ण रूप से संचालित हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने राजस्थान में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कोई संशोधित समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राजस्थान राज्य में, ई -न्यायालय मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग में, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से कार्यान्वित की जा रही है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय विहित मार्ग दर्शक सिद्धांतों और समय-सीमाओं

के अनुरूप परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी उपाय कर रहा है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना, केस सूचना प्रणाली (सीआईएस), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, ई-फाइलिंग, ई-सेवा केंद्र और अन्य पहलों सहित परियोजना के विभिन्न घटकों को व्यवस्थित रीति से लागू किया जा रहा है। परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और सभी हितधारकों को परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से न्यायिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखा जाता है।

(ख) : विभिन्न सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहलों के लिए ई-न्यायालय परियोजना की जिलावार कार्यान्वयन स्थिति उपाबंध-1 में संलग्न है।

(ग) : 1471 न्यायालयों में ई-फाइलिंग सुविधा है। 1376 न्यायालयों में आभासी सुनवाई /वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है। 1425 न्यायालयों में न्यायिक अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण सुविधा संक्रिय है।

(घ) : ई-न्यायालय परियोजना के चरण 3 की शुरुआत 2023 में मार्च 2027 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी। अभी तक कोई संशोधित समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

****

उपाबंध 1

राजस्थान में ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1386 जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

राजस्थान राज्य में ई-न्यायालय परियोजना की जिलावार कार्यान्वयन स्थिति:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सीआईएस कार्यान्वयन	वी सी प्रसुविधा की उपलब्धता	ई-सम्मन (एनएसटीपी और त्वरित)	ई-फाइलिंग और ई-पे वितरण	स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन	आईसीजेएस*	ई-सेवा केंद्र	सौर	न्यायालय परिसर और न्यायालयों में हार्डवेयर इंस्टालेशन
लक्ष्य		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	92	109	(हां/नहीं)
1	अजमेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
2	अलवर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	-	हाँ
3	बाड़मेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	-	हाँ
4	बांसवाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
5	बारां	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	7	हाँ
6	भरतपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	-	हाँ
7	भीलवाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	4	हाँ
8	बीकानेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	2	हाँ
9	बूंदी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	8	5	हाँ
10	चित्तौड़गढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	5	10	हाँ
11	चुरू	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
12	दौसा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	1	हाँ
13	धौलपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	1	हाँ
14	डूंगरपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	4	हाँ
15	हनुमानगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	3	हाँ
16	जयपुर जिला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	5	हाँ
17	जयपुर मेट्रो I	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	4	हाँ
18	जयपुर मेट्रो II	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	1	हाँ
19	जैसलमेर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	3	हाँ
20	जालौर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	-	हाँ
21	झालावाड़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	3	हाँ
22	झुंझुनू	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	-	हाँ
23	जोधपुर जिला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	-	हाँ
24	जोधपुर मेट्रो	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	1	हाँ
25	करौली	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	1	हाँ
26	कोटा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	4	हाँ
27	मेर्टा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	2	हाँ
28	पाली	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	5	हाँ

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सीआईएस कार्यान्वयन	वी सी प्रसुविधा की उपलब्धता	ई-सम्मन (एनएसटीपी और त्वरित)	ई-फाइलिंग और ई-पे वितरण	स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन	आईसीजेएस*	ई-सेवा केंद्र	सौर	न्यायालय परिसर और न्यायालयों में हार्डवेयर इंस्टालेशन
लक्ष्य		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	92	109	(हां/नहीं)
29	प्रतापगढ़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	1	हाँ
30	राजसमंद	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	3	हाँ
31	सहाँ माधोपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	3	हाँ
32	सीकर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	3	हाँ
33	सिरोही	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	2	हाँ
34	श्री गंगानगर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	2	हाँ
35	टोंक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	1	3	हाँ
36	उदयपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	3	हाँ
37	ब्यावर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	इन नवनिर्मित न्यायधीश परिषद के अभिलेख अब भी पुरानी न्यायदहीस परिषद में उपलब्ध है	हाँ	1	2	हाँ
38	बालोतरा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	2	हाँ
39	खैरथल-तिजारा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	2	2	हाँ
40	कोटपुतली-बहरोड़	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	1	3	हाँ
41	डीडवाना-कुचामन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	1	1	हाँ
42	डीग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	-	हाँ
43	फलौदी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	-	हाँ
44	सलूम्बर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	-	1	हाँ
	कुल							50	103	

(स्रोत : ई-कमेटी, भारतीय उच्चतम न्यायालय)

आईसीजेएस*: अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली

****